sphere needs special attention. Agricultural marketing also needs to be improved with proper development of rail, road, cold storage, markets, etc. Also, credit facilities are not smoothly available to the MSE sector. A fifteen per cent tax rebate on setting up of new industries, which Backward Districts are entitled to, would greatly help in the development of the area and raise the standard of lives of the people.

I would urge upon the Government to include Cooch Behar, and other districts in the country, which have more than 50 per cent SC/ST population, in the BRGF Scheme for all-round development of the district and to improve the lives of the people. I would also like to bring the attention to the worrying fact that West Bengal is still owed 40 per cent Central funds for BRGF over the last five years.

Demand to give reservation to fishermen in employment in Central and the provincial police forces in the country

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, पूरे देश में प्रति वर्ष अधिक वर्षा के कारण नदियों में भयंकर बाढ़ आ रही है, जिससे हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़ के कारण लोगों की जानें चली जाती हैं, क्योंकि देश में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने हेतु पुलिस फोर्स नहीं है और न ही राज्यों में केन्द्रीय पुलिस बल है, जिन्हें बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का तकनीकी ज्ञान हो। इसलिए जन्मजात फिशरमैन जो समुद्र या नदी में ज्यादातर मछली के शिकार हेतु सैकड़ों किलोमीटर समुद्र में चले जाते हैं तथा नदियों में बाढ़ के समय काम करते हैं, उन्हें सेना तथा राज्य पुलिस में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे दैवी आपदा बाढ़ के समय, देश की जन हानि को बचाने में काम कर सकें।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्रीय पुलिस बल व प्रांतीय पुलिस बल में 50 प्रतिशत का आरक्षण पेशेवर जन्मजात फिशरमैन बेरोज़गारों को देकर बाढ़ से बचाने हेतु अलग से पुलिस बल की स्थापना की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Avinash Pande. ...*(Interruptions)*... Shri Avinash Pande - not present. ...*(Interruptions)*... Chaudhary Munvvar Saleem. ...*(Interruptions)*...

Demand for early sanctioning of funds for cleaning the river Ganga in Uttar Pradesh

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर उस गंगा की पाकीज़गी का सवाल लेकर खड़ा हुआ हूं, जो महान भारत का इतिहास, संस्कृति और धर्म मानी जाती है। अपने प्रदूषण को लेकर कराहती हुई गंगा, केन्द्र सरकार से उम्मीद कर रही है कि सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। मैंने आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व दिनांक 11 मार्च, 2013 को गंगा तथा अन्य नदियों को जहरीला बनाने वालों के विरुद्ध संविधान संशोधन के माध्यम से सख्त कानूनी कार्यवाही की भी बात कही थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि महाकुंभ के दौरान नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के मुस्लिम व्यवस्थापक के रूप में स्वच्छ पानी में श्रद्धालुओं को स्नान करा कर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि सरकार भरपूर सहयोग दे तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।